



## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की स्थिति

---

## दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की स्थिति

### संदर्भ

- दक्षिण एशिया, विश्व की पांचवीं से अधिक जनसंख्या का निवास स्थान होने तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध होने के बावजूद, विश्व में आर्थिक रूप से सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है।

### दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था की स्थिति

- दक्षिण एशिया** — दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देश शामिल हैं, जिनकी जनसंख्या 1.8 बिलियन से अधिक है तथा इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है।
  - यूरोपीय संघ (EU):** \$18 ट्रिलियन (केवल 5.8% वैश्विक जनसंख्या के साथ)
  - NAFTA:** \$24.8 ट्रिलियन
- विकास के बीच विभाजन**
  - भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग, अवसंरचना निवेश और डिजिटल नवाचार से मज़बूती से उभरी है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
  - बांग्लादेश ने वस्त्र निर्यात और प्रवासी प्रेषणों में स्थिर वृद्धि बनाए रखी है।
  - श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों ने आर्थिक संकट, उच्च मुद्रास्फीति और ऋण संकट का सामना किया — जो क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है।
- क्षेत्रीय व्यापार में कमी** दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के अंतर्गत अंतर-क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार का केवल 5% से 7% है - जो विश्व स्तर पर सबसे कम है।
  - यह यूरोपीय संघ (45%), आसियान (22%) और NAFTA (25%) से बहुत नीचे है।
  - उच्च टैरिफ, खराब कनेक्टिविटी और नौकरशाही लालफीताशाही सीमा पार व्यापार को हतोत्साहित करती है।
- व्यापार अंतराल:** बांग्लादेश (93% अपूर्ण संभावना), पाकिस्तान (86%) और अफगानिस्तान (83%) जैसे देशों में सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं।
  - साथ ही, ट्रेड-टू-GDP अनुपात 2022 में 47.3% से घटकर 2024 में 42.94% हो गया — क्षेत्रीय निर्भरता में गिरावट दर्शाता है।
- पड़ोसी होने की उच्च लागत**
  - SAARC के अंदर व्यापार लागत:** वस्तु मूल्य का 114%
  - अमेरिका से व्यापार लागत:** 109%
  - भारत-पाकिस्तान व्यापार लागत:** भारत-ब्राज़ील व्यापार से 20% अधिक, जबकि ब्राज़ील 22 गुना दूर है
  - ASEAN का आपसी व्यापार व्यय:** 76% — SAARC की तुलना में 40% सस्ता
- छूटे अवसर:** दक्षिण एशिया का वर्तमान अंतर-क्षेत्रीय व्यापार सार्क देशों के बीच लगभग 23 बिलियन डॉलर है, जो संभावित 67 बिलियन डॉलर से काफी कम है, तथा 2020 के लिए UNESCAP द्वारा चिन्हित अनुमानित 172 बिलियन डॉलर की क्षमता से भी काफी कम है।

## अन्य प्रमुख चुनौतियाँ

- भूराजनीतिक तनाव और अविश्वासः लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता - विशेषतः भारत और पाकिस्तान के बीच - ने सार्क और साफ्टा जैसी क्षेत्रीय सहयोग पहलों को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया है।
  - राजनीतिक असहमति प्रायः आर्थिक निर्णय लेने में भी फैल जाती है।
- संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ: उच्च टैरिफ, प्रतिबंधात्मक कोटा और गैर-टैरिफ बाधाएं पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को हतोत्साहित करती हैं।
  - कई दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने परस्पर निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है।
- खराब संपर्क और अवसंरचना: अपर्याप्त परिवहन संपर्क, बोग्डिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और अविकसित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं एवं लोगों के प्रवाह को सीमित करते हैं।
- सदस्य देशों में असंतुलनः क्षेत्र में भारत के आर्थिक प्रभुत्व ने शक्ति असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, जिससे छोटे देशों में असमान लाभ और प्रभाव को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
- कमज़ोर संस्थागत ढाँचा: क्षेत्रीय सहयोग तंत्र में प्रायः क्षमता, प्रवर्तन क्षमता या एकीकरण के वादों को पूरा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी होती है।
  - उदाहरण के लिए, सार्क काफी हद तक निष्क्रिय रहा है।
- चीन का बढ़ता प्रभाव: बाहरी शक्तियों, विशेषकर चीन की बढ़ती हुई भागीदारी के कारण कुछ दक्षिण एशियाई देश अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की अपेक्षा द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देने लगे हैं।
- जलवायु जोखिमः यह क्षेत्र बाढ़ से लेकर उष्ण वायु तक जलवायु संबंधी आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे कृषि और आजीविका को खतरा है।

## दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में भारत की पहलें

- विकास साझेदारी और क्रण की लाइनें: बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए, जिसमें नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ सड़क तथा रेल संपर्क, बिजली-साझाकरण समझौते और श्रीलंका और मालदीव में बंदरगाह विकास शामिल हैं।
- बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाएः: भारत-बांग्लादेश मैत्री पावर प्लांट, भारत-नेपाल क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (भारत को म्यांमार और उससे आगे जोड़ना) जैसी परियोजनाएं क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- सार्क विकास कोष : यह ऊर्जा, परिवहन और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
- बिम्सटेक और बीबीआईएन पहलः इन उप-क्षेत्रीय समूहों का उद्देश्य व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना है।
- स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल आउटरीचः भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल ने सीमा पार सहयोग को प्रेरित किया है, जिसमें भारतीय इनक्यूबेटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पड़ोसी देशों के उद्यमियों को सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं।

### आगे की राह:

- राजनीतिक क्षेत्रीयता (Strategic Regionalism) दक्षिण एशिया के विकास की कुंजी वास्तविक क्षेत्रीय सहयोग में है। इसके लिए आवश्यक है:
  - SAFTA में सुधार और कार्यान्वयन पर बल;
  - सीमा और विश्वास के मुद्दों का समाधान निरंतर कूटनीति के माध्यम से;
  - क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाएँ बनाना ताकि रोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिले;
  - व्यापार अवसंरचना का विकास जो एकीकरण को प्रोत्साहित करे, न कि विभाजन को;
  - राजनीतिक विवादों से आर्थिक सहयोग को अलग करना — जैसा कि यूरोपीय संघ के मॉडल में देखा गया है।

Source: TH

### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की विफलता में राजनीतिक प्रतिदंडिता और ऐतिहासिक तनाव किस सीमा तक योगदान करते हैं, और साझा समृद्धि को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय हितधारक इन चुनौतियों पर किस प्रकार नियंत्रण पा सकते हैं?

